संपादकीय जागरण

बुधवार, 6 दिसंबर, 2017 : पौष कृष्ण 3 वि. 2074

आत्मबल ही विपत्ति में सबसे बड़ा सहायक होता है

अयोध्या पर अड़ंगेबाजी

यह अच्छा नहीं हुआ कि अयोध्या विवाद की सुनवाई करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बेवजह अड़ंगे लगाने का काम किया गया। समझना कठिन है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल के यह कहने का क्या मतलब था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख भाजपा के घोषणा पत्र में होने के कारण इस मसले की सुनवाई अगले आम चुनाव के बाद होनी चाहिए? क्या उन्हें यह पता है कि अगले आम चुनाव के बाद भाजपा राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणापत्र में स्थान नहीं देगी या फिर वह यह चाह रहे कि जब तक राम मंदिर भाजपा के एजेंडे में रहता है तब तक इस मसले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर जब उच्च न्यायालय ने अयोध्या मसले पर होने वाली राजनीति की कहीं कोई परवाह नहीं की और अपना फैसला दिया तब फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आम तौर पर किसी मसले पर दोनों पक्ष इसलिए अदालत जाते हैं कि मामले का निपटारा हो जाए, लेकिन अयोध्या प्रकरण में यही दिख रहा है कि एक पक्ष की दिलचस्पी मामले को लटकाने और इसके लिए तरह-तरह के बहाने बनाने में है। यह दलील बहानेबाजी के अलावा और कुछ नहीं कि अदालती कार्यवाही इसलिए टाली जाए, क्योंकि मामला राजनीतिक हो चुका है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि यह दलील राजनीति में सक्रिय और राजनीतिक मसलों को अदालत ले जाने वाले वकील की ओर से दी गई? जो मसला सैकड़ों साल पुराना हो और जिस पर उच्च न्यायालय सात साल पहले फैसला सुना चुका हो उस पर ऐसे बेजा सवाल उठाने वालों के इरादे भांपना मुश्किल नहीं कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है?

यह राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले को अनंतकाल तक टालने वाली बहानेबाजी पर गौर नहीं किया, लेकिन अच्छा होता कि दस्तावेजों के आदान-प्रदान न होने के चलते भी सुनवाई को फरवरी तक के लिए स्थगित नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए, क्योंकि दस्तावेजों का अनुवाद और उनके आदान-प्रदान की प्रक्रिया शेष रहने की दलीलें अड़ंगेबाजी का ही हिस्सा अधिक जान पड़ती हैं। कम से कम अब तो सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि आगे कोई भी अड़ंगा न लगने पाए। उसे सभी ऐतिहासिक, पौराणिक और अदालती दस्तावेजों के साथ पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों का भी गहन अध्ययन सुनिश्चित करना चाहिए। पुरातत्व विभाग के दस्तावेज दूध का दूध और पानी का पानी करने में अहम भूमिका निभाने के साथ उन्हें बेनकाब करने वाले भी साबित होंगे जो यह जानते हुए भी अनजान बने रहना चाहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर किया गया। निःसंदेह वे यह भी जानते हैं कि अयोध्या और राम एक-दूजे के पर्याय हैं और ढांचा ध्वंस के दशकों पहले से विवादित स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। अयोध्या मसले को राजनीतिक बताकर उसकी सुनवाई टालने की कोशिश करने वाले यह समझें तो बेहतर कि राजनीतिक दलों के रवैये के कारण ही यह मसला सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा है। अयोध्या मसले का अब तक अनसुलझा रहना यही अधिक बताता है कि हमारे राजनीतिक दल समाज को दिशा दिखाने में नाकाम रहे।

भविष्य की खातिर

प्रदेश सरकार 21-22 फरवरी को होने वाले 'इन्वेस्टर्स समिट' के पहले इसके लिए 'इलेक्ट्रिक व्हीकल' (ईवी) पालिसी लाएगी। शुरुआत में इन वाहनों की चार्जिंग के लिए पेट्रोल पंपों पर व्यवस्था होगी। बाद में इसके लिए अलग संरचना बनायी जाएगी। सरकार का जोर सौर ऊर्जा के अधिकतम प्रयोग पर रहेगा। 'इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में दस हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। स्वचालित वाहनों जैसे- मोटर, ट्रक, बस, विमान, ट्रैक्टर तथा अन्य प्रकार की अनेक मशीनों में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अदग्ध हाइड्रोकार्बन, सीसा व अन्य विषैली गैसें वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करती हैं।

बैटरी चालित वाहनों का अधिकाधिक उपयोग की सरकार की मंशा निसंदेह प्रसंशनीय तो है, साथ ही भविष्य के खतरों के प्रति सचेत भी करने वाली है

दरअसल बैटरी चालित वाहनों का उत्सर्जन शून्य होता है। बढ़ती आबादी और मांग के अनुसार सरकार अगर अपनी नीति पर सही तरीके से अमल करा पाती है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ऐसे वाहनों के उत्पादन का हब बन सकता है। सरकार की मंशा भी यही है। देश और प्रदेश इस समय प्रदूषण की विकराल समस्या से जूझ रहा है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन प्रदूषण की समस्या और भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे हालात में वस्तुतः बैटरी चालित वाहन किसी वरदान से कम नहीं। 'इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड' और जार्जटाउन विश्वविद्यालय में किए गए शोध के अनुसार अमेरिका, कनाडा सहित कई विकसित देशों में वर्ष 2040 तक 90 फीसद से अधिक वाहन बैटरी चालित ही होंगे। ऐसे में बैटरी चालित वाहनों का अधिकाधिक उपयोग किए जाने की सरकार की मंशा निसंदेह प्रसंशनीय तो है, साथ ही भविष्य के खतरों के प्रति सचेत भी करने वाली है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ईरान में चाबहार बंदरगाह के संचालन से भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने में सफल होगा?

आज का सवाल
क्या आपको लगता है कि सरकारें प्रदूषण की समस्या को लेकर गंभीर नहीं हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

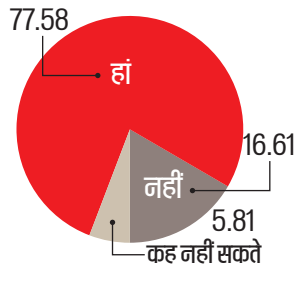

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

राहुल गांधी का मंदिर अभियान

ए सूर्यप्रकाश

क्या खुद को शिवभक्त बताने वाले राहुल कांग्रेस को अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू की छद्म सेक्युलर और हिंदू विरोधी विरासत से मुक्त कर सकेंगे?

कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे राहुल गांधी का हालिया सोमनाथ दौरा विवादों में घिर गया। राहुल का यह दौरा यह दर्शा गया कि चुनावी दौर में मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता किस हद तक जा सकते हैं। यह साफ है कि राहुल गांधी चुनावी फायदे के लिए ही मंदिरों की खाक छानते फिर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि खुद को शिवभक्त बताने वाले राहुल क्या कांग्रेस पार्टी को अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू की छद्म सेक्युलर और हिंदू विरोधी विरासत से मुक्त कर सकेंगे? राहुल का 'सोमनाथ अभियान' परवान न चढ़ने की एक प्रमुख वजह यह है कि भारत अभी भी नहीं भूला है कि देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने उस सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में हरसंभव अड़ंगे लगाने का काम किया जिस मंदिर को महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के अलावा खुद को इस्लाम के योद्धा होने का दावा करने वाले तमाम आततायियों ने कई बार लूटने का काम किया। आजादी के बाद बहुमत इसी पक्ष में था कि अगाध श्रद्धा के केंद्र सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराकर राष्ट्रीय गौरव को बहाल किया जाए, लेकिन नेहरू सरकार इस पवित्र स्थल को जीर्णशीर्ण अवस्था में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआइ को सौंपने की फिराक में थी कि वही इसका संरक्षण करे। हालांकि नेहरू सरकार का हिस्सा रहे सरदार पटेल, केएम मुंशी और एनवी गाडगिल के अलावा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके विरोध में थे और उन्होंने एलान किया कि राष्ट्र का गौरव तब तक बहाल नहीं हो सकता जब तक सोमनाथ का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माने जाने वाले सोमनाथ लिंग की पुनर्स्थापना नहीं हो जाती। भारत में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदू मंदिरों को विध्वंस किए जाने के रक्तरंजित इतिहास को देखते हुए इन सभी का मानना था कि जब तक सोमनाथ मंदिर को अपना पुराना स्वर्णिम वैभव नहीं मिलेगा तब तक भारत का राष्ट्रीय स्वाभिमान बहाल नहीं हो सकेगा, लेकिन नेहरू अपने रुख पर अड़े थे। वह इस आधार पर विरोध करते रहे कि इससे उनकी सरकार की सेक्युलर साख को नुकसान पहुंचेगा।

सोमनाथ को लेकर नेहरू की आपत्तियों ने न केवल सरदार पटेल के साथ उनके समीकरण गड़बड़ा दिए, बल्कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और उनकी कैबिनेट के ही एक अन्य सदस्य केएम मुंशी के साथ भी उनकी कटुता बढ़ा दी। नेहरू की पहली आपत्ति यह थी कि सरकारी पैसे से यह काम नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने अपनी सरकार के सदस्यों और राष्ट्रपति से कहा कि उन्हें इस परियोजना से नहीं जुड़ना चाहिए। इस पर सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से अनुनय-विनय की। महात्मा ने इसे पूरा समर्थन तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी कि यह काम सरकारी पैसे से नहीं, बल्कि जनता से जुटाए पैसे से बने ट्रस्ट के जरिये पूरा किया जाए। नेहरू की आपत्तियों से प्रभावित हुए बिना पटेल, मुंशी और गाडगिल ने तुरंत कदम उठाते हुए ट्रस्ट का निर्माण किया जिसमें जनता से पैसे जुटाकर पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। इस परियोजना से न जुड़ने की नेहरू की सलाह को उन्होंने दरकिनार कर दिया। सरदार पटेल ने एलान किया कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का काम बेहद पुण्य का है जिसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। केएम मुंशी ने पटेल के एक पत्र का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा, 'इस मंदिर को लेकर हिंदू भावनाएं बहुत व्यापक और प्रबल हैं.. ऐसे में मंदिर का कायाकल्प बहुत सम्मान की बात होगी।'

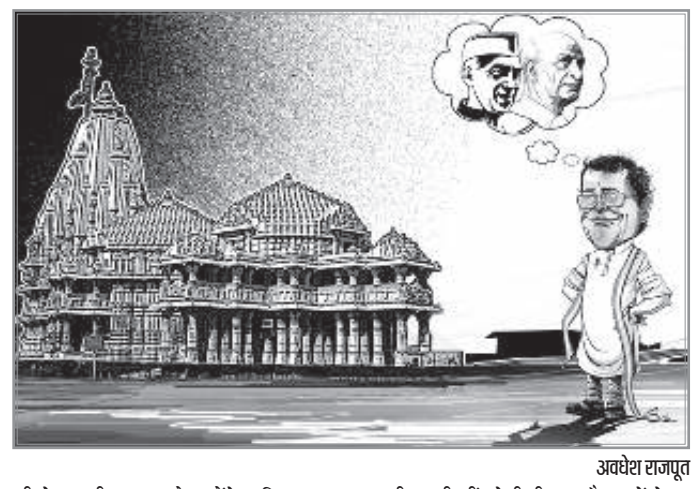

अवधेश राजपूत

अफसोस की बात यह रही कि सरदार पटेल अपने इस सपने को पूरा होते नहीं देख सके, क्योंकि 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। हालांकि मंदिर का काम पूरी तेजी से आगे बढ़ा और प्रशासक भी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के लिए तैयार हो गए। नेहरू ने इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की भागीदारी पर एतराज जताया। प्रसाद ने नेहरू की बिन मांगी सलाह को अनसुना कर मंदिर के कार्यक्रम में भाग लिया। इस पर नेहरू ने कहा कि सोमनाथ के कायाकल्प से उनकी सरकार का कोई लेनादेना नहीं है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मुंशी को भी नेहरू के कोप का भाजन बनना पड़ा। कैबिनेट बैठकों में उन्हें नेहरू की झिड़कियां सुननी पड़ती थीं। ऐसी ही एक बैठक में नेहरू ने इसे 'हिंदू पुनरोत्थान' की परियोजना करार दिया, लेकिन मुंशी अपने रुख पर अडिग रहे। 24 अप्रैल, 1951 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की तुलना में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर भारत की सामूहिक जनचेतना कहीं अधिक प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि इसके उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सरदार पटेल को भी शामिल होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश परियोजना पूरी होने से पहले ही उनका निधन हो गया। किसी अन्य भावना के अलावा हमें यह भी महसूस होता है कि सरदार के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमें पूरी क्षमता के साथ इसमें मदद करनी चाहिए।

चूंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि उद्घाटन समारोह के लिए सरकारी पैसा खर्च किया जाए इसलिए मुंशी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सोमनाथ ट्रस्ट फंड और जनता से लिया चंदा ही खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। अपने पत्र का समापन करते हुए उन्होंने लिखा, 'यह अतीत में मेरा विश्वास ही है जिसने मुझे वर्तमान में काम करने की क्षमता और भविष्य की ओर देखने की दृष्टि प्रदान की। अगर स्वतंत्रता मुझे भगवद गीता से दूर करती है या करोड़ों लोगों के मंदिरों में विश्वास से वंचित रखती है तो ऐसी स्वतंत्रता मेरे लिए मायने नहीं रखती। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अपने शाश्वत स्वप्न को पूरा करने का मुझे सौभाग्य मिला। यह मुझे आश्वस्त करता है और मैं इस बात को लेकर एकदम निश्चिंत भी हूं कि जब यह धार्मिक स्थल हमारे जीवन में पुनः वही महत्ता हासिल कर लेगा तो इससे हमारी जनता को न केवल धर्म का विशुद्ध भाव मिलेगा, बल्कि आजादी के इस दौर और आने वाले वक्त में भी हमारी शक्ति की और प्रबल चेतना की भावनाएं भी मजबूत करेगा।'

अगर नेहरू और उनकी कांग्रेस पार्टी पटेल और मुंशी की बात सुन लेती तो आज नेहरू के राजनीतिक वंशज को अपनी पार्टी की हिंदूवादी जड़ों को दिखाने के लिए इतने जतन नहीं करने पड़ते। नेहरू की आपत्तियों को किनारे कर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई, 1951 को सोमनाथ मंदिर में लिंगम स्थापना समारोह में भाग लिया। वहां उन्होंने कहा कि भले ही कुछ स्थलों को ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन अपनी संस्कृति और विश्वास के साथ लोगों के रिश्ते को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। असल में राहुल गांधी के अचानक सोमनाथ के शरणागत होने ने हमें इस मंदिर और हिंदू भावनाओं को लेकर नेहरू के रुख और उनकी कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी छद्म धर्मनिरपेक्ष नीतियों वाले रवैये का स्मरण करने पर मजबूर कर दिया है। कुल मिलाकर हिंदुओं को लेकर नेहरू के रुख या 'नेहरू सिद्धांत' के साक्ष्यों को देखकर यही लगता है कि सोमनाथ में राहुल गांधी का 'प्रायश्चित' देर से उठाया गया नाकाफी कदम है।

(लेखक प्रसार भारती के प्रमुख एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

तथ्यों को छिपाकर ईवीएम पर हमला

राजीव सचान

ईवीएम में खामी हो तो उसे उजागर करने में हर्ज नहीं, लेकिन छल-छद्म का सहारा लेना निकृष्ट राजनीति के अलावा और कुछ नहीं

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू हुआ रुदन अब तक जारी है। यह रुदन एक दिसंबर को उसी समय शुरू हो गया था जब यह स्पष्ट होने लगा था कि अन्य दलों के मुकाबले भाजपा बढ़त हासिल करती दिख रही है। शाम होते-होते इस रुदन ने और जोर पकड़ लिया और वह कर्कश विलाप में बदल गया। भाजपा की जीत में ईवीएम की भूमिका को संदिग्ध करार देकर विलाप करने वालों को उस समय और बल मिला जब सहारनपुर की निर्दलीय प्रत्याशी शबाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। इसमें वह यह कह रही थीं कि अरे, उन्हें जीरो वोट कैसे मिले? आखिर उनका खुद का और उनके घर वालों के वोट कहां गए? शबाना के इस वीडियो को ईवीएम में गड़बड़ी के पुख्ता सुबूत के तौर पर पेश किया जाने लगा। इस शरारती वीडियो को जिन लोगों ने सच करार देकर ईवीएम और चुनाव आयोग को जीभर कर कोसा उनमें कई जाने-माने लोगों के साथ-साथ वकील प्रशांत भूषण भी शामिल थे। कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के कई नेता एवं समर्थक भी इस वीडियो को सच की तरह पेश कर रहे थे। अगले दिन जब यह खबर आई कि शबाना को तो 87 वोट मिले हैं और शून्य वोट मिलने का उनका दावा निरा खोखला है तो उनके फर्जी वीडियो के बहाने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा।

शबाना के झूठ की पोल खुल जाने के बावजूद सोशल मीडिया और मीडिया में इस तरह की खबरें आती रहीं कि ईवीएम ने भाजपा को लाभ पहुंचाया है। इन खबरों को आधार प्रदान किया अखिलेश, मायावती और राजबब्बर सरीखे नेताओं के उन बयानों ने जिनके जरिये यह कहने की कोशिश की जा रही थी कि निकाय चुनावों में जहां ईवीएम से मतदान हुआ वहां तो भाजपा ने बढ़त हासिल की, लेकिन जहां बैलट पेपर से मतदान हुआ वहां उसका प्रदर्शन फीका रहा। चूंकि ऐसे बयान अखिलेश और मायावती ने दिए इसलिए मीडिया ने बगैर कोई छानबीन किए उन्हें प्रमुखता प्रदान की। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता के बीच यह संदेश गया कि हो न हो, ईवीएम ने गुपचुप तौर पर भाजपा का भला किया है। इसके बाद सोशल मीडिया और विशेष रूप से ट्विटर पर यह कहने की होड़ मच गई कि जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं। इसी के साथ भाजपा और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ को रेखांकित किया जाने लगा। इस क्रम में यहां तक कहा गया कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है। तीन दिसंबर को ट्विटर पर 'ईवीएम है तो बीजेपी है' को जमकर ट्रेंड किया गया। किसी ने और यहां तक कि मीडिया के एक बड़े हिस्से ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस आरोप में कितनी सत्यता है कि जहां ईवीएम से मतदान हुआ वहां तो भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जहां बैलट पेपर से मतदान हुआ वहां वह पिछड़ गई। एक तरह से कौआ कान ले गया वाली उक्ति खुशी-खुशी चरितार्थ की गई और वह भी तब जब उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव नतीजों का सारा कच्चा-चिट्ठा आ गया था। चुनाव आयोग के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं कि जहां ईवीएम से वोट पड़े वहां भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन वे इसकी भी पुष्टि करते हैं कि जहां बैलट पेपर से मतदान हुआ वहां भाजपा के साथ-साथ सपा, बसपा और कांग्रेस का प्रदर्शन भी फीका रहा। बतौर उदाहरण ईवीएम से हुए निगम पार्षदों के चुनाव में यदि जीते भाजपा प्रत्याशियों का प्रतिशत करीब 45 रहा और सपा, बसपा एवं कांग्रेस का क्रमशः 15, 11 और 8 तो बैलट पेपर से हुए पालिका सदस्यों के चुनाव में जहां भाजपा के जीते प्रत्याशियों का प्रतिशत 17 रहा तो सपा, बसपा और कांग्रेस के जीते प्रत्याशियों का प्रतिशत क्रमशः 9, 5 और 3 रहा। ठीक ऐसी ही स्थिति पंचायत सदस्यों की जीत के प्रतिशत की रही।

पार्टी	जीते निगम सदस्य (ईवीएम)	जीते पालिका सदस्य (बैलट)	जीते पंचायत सदस्य (बैलट)
भाजपा	45.85%	17.53%	12.22%
बसपा	11.31%	4.98%	4.01%
सपा	15.54%	9.07%	8.34%
कांग्रेस	8.46%	3.00%	2.32%

आंकड़ों से यह साफ है कि जहां ईवीएम से मतदान हुआ वहां भाजपा की तरह सपा, बसपा और कांग्रेस के जीते प्रत्याशियों का भी प्रतिशत अधिक रहा और जहां बैलट पेपर से मतदान हुआ वहां भाजपा की तरह बाकी दलों के जीते प्रत्याशियों का भी प्रतिशत कम रहा। इस तथ्य को बड़ी चतुराई और सफाई से छिपाया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि बैलट पेपर से हुए मतदान में भाजपा के मुकाबले अन्य दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा और इस तरह यह साबित हो गया कि ईवीएम ने भाजपा को लाभ पहुंचाया। ईवीएम विरोधी शरारत भरे दुष्प्रचार की पोल इस तथ्य से भी खुलती है कि बैलट पेपर से हुए मतदान वाले पालिका और पंचायत चुनाव में जहां भाजपा के जमानत जब्त होने वाले प्रत्याशियों का प्रतिशत 38 है वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों का क्रमशः 52, 73 और 87, लेकिन भूले से भी इसका उल्लेख न तो अखिलेश ने किया और न मायावती ने और न ही उनके साथियों ने। कोई भी समझ सकता है कि अगर बैलट पेपर से हुए मतदान की हकीकत बयान की जाती तो ईवीएम को भाजपा की मदद करने वाली कथित करामाती मशीन करार देने में मुश्किल पेश आती। ईवीएम के खिलाफ तथ्यों को छिपाकर छेड़ा गया यह पहला अभियान नहीं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दौरान ही मेरठ में ईवीएम में कथित गड़बड़ी बताने वाला एक वीडियो सामने आया था। हालांकि यह वीडियो यही दर्शाता था कि कोई भी बटन दबाने पर भाजपा के चुनाव निशान के साथ-साथ नोटा निशान के समक्ष भी लाइट जलती थी, लेकिन सनसनी फैलाने के लिए यह प्रचारित किया गया कि भईया कोई भी बटन दबाओ, वोट तो भाजपा के खाते में ही जा रहा है।

ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कुछ राजनीतिक दल किस हद तक जाने को तैयार हैं, इसका एक उदाहरण तब भी मिला था जब आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया था। इस एक दिन के सत्र में एक नकली ईवीएम के जरिये बेहद भोंडे ढंग से यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि इस मशीन को हैक कर मनचाहे चुनाव नतीजे हासिल करना बायें हाथ का खेल है। ईवीएम हैक करने का तमाशा बीटेक डिग्री वाले एक विधायक ने किया था। बाद में यह विधायक चुनाव आयोग की चुनौती को स्वीकार करने से पीछे हट गया था। ईवीएम में कोई खामी हो तो उसे उजागर करने में हर्ज नहीं, लेकिन तथ्यों को छिपाकर या तोड़-मरोड़कर अथवा छल-छद्म का सहारा लेकर उसके खिलाफ माहौल बनाना निकृष्ट राजनीति के अलावा और कुछ नहीं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मश्लाघा

आत्मश्लाघा को मुहावरे की भाषा में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कहते हैं। अधिकांश लोग अपनी पीठ खुद ही थपथपाते दिखाई पड़ते हैं। कहीं किसी विशिष्ट कार्य की चर्चा हुई नहीं कि खुद को उससे विशिष्ट कार्य करते रहने की डींग हांकने लगते हैं। इन्हीं आदतों से वे लोगों के बीच मजाक के पात्र बनते हैं। दरअसल मनुष्य का अहं जब उसके सिर पर चढ़ जाता है तो वह जल्दी उतरता नहीं। वह जो नहीं है, वह दिखाना चाहता है। साथ ही बात-बात में यह भी लोगों के बीच जताता है कि वह बहुत चालाक और बुद्धिमान है। ऐसे लोग बात-बात में यह कहते दिख जाएंगे कि मैंने ऐसा दांव मारा, ऐसी चालाकी दिखाई, ऐसी तिकड़म भिड़ाई कि किसी की दाल नहीं गलने दी। इसके विपरीत श्रेष्ठ जन इस तरह की आदतों से बचते हैं। दिखाई तो पड़ते हैं बहुत सामान्य, लेकिन होते हैं विशिष्ट। जिसका नतीजा होता है कि जब वे कोई बड़ा कार्य कर जाते हैं, तब लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं।

मनुष्य को चाहिए कि वह यत्र-तत्र-सर्वत्र मैं श्रेष्ठ हूं, बड़े से बड़ा कार्य मैं ही कर सकता हूं-सरीखी डींग नहीं हांके। थोड़ी देर के लिए मान लें कि डींग तो हांक दी, लेकिन कार्य नहीं कर सके तो उपहास के पात्र बनने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हर काल में अनेक ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे कि आत्मश्लाघा करने वाले पराजित होते रहे हैं, जबकि विनम्र महापुरुष जो भी काम शुरू किए उसमें सफल होते रहे। महात्मा गांधी, महामना मदनमोहन मालवीय जैसे महापुरुष अहंकार की भावना से कोसों दूर रहे। लिहाजा क्रूर ब्रिटिश शासकों को घुटने टेकने के लिए उस काल के महापुरुषों ने विवश कर दिया। सामान्य सा जीवन जीने वाले महामना मदनमोहन मालवीय ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित किया जो किसी अहंकारी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। मालवीय जी विश्वविद्यालय के लिए अपमानजनक स्थितियों का सामना करने के बावजूद विचलित नहीं हुए। सफलता विनम्र भाव से और एकजुट होकर कार्य करने से मिलती है। अहंकारी व्यक्ति खुद को बड़ा और कार्य को छोटा मान लेता है, जबकि किसी भी कार्य में सुविचारित योजना, टीम भाव होता है, तब लोगों का सहयोग और शुभकामनाएं मिलती हैं, जो किसी पूंजी से कम नहीं हैं।

साकेत पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

आपसी सद्भाव जरूरी

अयोध्या मसले पर अवसर गंवाने का काम शीर्षक से लिखे अपने लेख में रामिश सिद्दीकी ने अयोध्या मसले के समाधन के लिए आपसी सद्भाव और इस्लाम के वास्तविक समानता के अर्थ को उजागर करते हुए भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक संदेश दिया है। सदियों से चले आ रहे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद ने तब तूल पकड़ा जब दोनों समुदाय अपने-अपने धर्मालयों के स्थानांतरण को स्वीकारने के पक्ष में नहीं थे। जिसके कारण कई निर्दोषों को अपनी जांन भी गंवानी पड़ी, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान आपसी सद्भाव है न कि हिंसा। भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म मानवता है। यदि इसी तथ्य को ध्यान में रखकर समस्या का हल खोजा जाय तो शायद इसके दलदल से दोनों समुदायों को निकाला जा सकता है।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

दहेज न लेने से निकलेगा हल

राजस्थान के कोटा शहर में डॉक्टर लड़के ने दहेज में एक करोड़ रुपये मांगे तो दुल्हन ने स्टेज से बरात लौटा दी। लड़की खुद डॉक्टर है और सगाई के वक्त काफी कुछ मांगे पूरी की जा चुकी थीं, फिर भी दहेज की मांग हुई? अभी भी दहेज रूपी दानव समाज को ठगे जा रहा है। लड़की चाहे अशिक्षित हो या अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो लेकिन रिश्ते के बीच दहेज जरूर रहेगा। आजकल की लड़कियां साहस करके बरात लौटा देती हैं, लड़के वालों को अपना अपमान सहना मंजूर है, फिर भी दहेज लेने का मोह रहता है। अब वो युग गया जब लड़कियां चुपचाप सह लेती थीं, अब बिटिया काबिल बन चुकी है। घर के पुरुषों के बराबर कमा रही है। तो क्यों दहेज लोभियों के घर में शादी क्यों करें? जरूरत है बहू को इज्जत से बिना दहेज के घर लाएं तो वो जीवन भर आपका सम्मान करेंगी।

अर्चना खंडेलवाल, नोएडा

गरिमा के विपरीत

मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति के जन्मदिन पर राज्यपाल रामनाईक द्वारा उनके आवास पर जाकर बधाई देने का कोई औचित्य नहीं था। जो व्यक्ति अपने को राम भक्तों का हत्यारा कहने में गर्व का अनुभव करता हो, जिसकी राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित हो, जो खुलेआम कहता हो कि मुस्लिमों के वोट मिलने के पश्चात भी विधानसभा चुनावों मे हमे मात्र 44 सीट क्यो मिलीं ? जातिवाद को प्रश्रय देता हो। मुस्लिम यादव के मत पाकर राज करने की योजना बनाता हो। ऐसे व्यक्ति भरोसेमंद कैसे हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के आवास पर जाकर महामहिम द्वारा बधाई देना उचित नहीं है।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

काश लचीला रवैया अपनाता मुस्लिम समाज

अयोध्या मसले पर अवसर गंवाने का काम शीर्षक से राशिम सिद्दीकी ने मर्मस्पर्शी भावनात्मक लेख लिखा है। वास्तव में यदि देश के तत्कालीन और वर्तमान मुसलिम नेतृत्व ने तनिक भी लचीला रवैया अपनाया होता, तो शायद बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक और अराध्य मर्यादापुरूषोतम भगवान राम लला को 68 वर्षों से भी अधिक समय से 'टैन्ट' मैं नहीं रहना पड़ता। हिंदुओं की सहनशीलता और आपसी भाईचारे की असहनीय मिसाल देखिए, कि भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा खोदाई से प्राप्त मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाए जाने के जीवन्त अवशेषों को साक्ष्य के उपरांत भी चंद मुट्ठी भर लोगों के दबाव के सम्मुख हमारे राजनेता और प्रखर हिन्दुवादी नतमस्तक हैं। 'अभी भी अयोध्या मसले पर नरम रवैया अपना कर भारत का मुस्लिम नेतृत्व विश्व में रह रहे सभी मुस्लिमों के लिए अनुकरणीय बन सकता है'।

mahendralalchamoli@gmail.com

पूरे देश में लागू हो यह कानून

मध्यप्रदेश विधानसभा ने वो विधेयक पास कर दिया जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा का प्रावधान था, ये पहल स्वागत योग्य है। इसे पूरे देश में कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। अखबारों में जब छोटे-छोटे बच्चों से दुष्कर्म की खबरे आती हैं, रूह कांप जाती है, यह सोचने की हिम्मत भी नहीं होती कि उन मासूमों ने किस दर्द को झेला है ऐसे अपराध करने वाले लोग किसी भी तरह इंसान कहलाने लायक नहीं, वो मानवता पर कलंक हैं। सच बात कहें तो फांसी भी उनके लिए उतनी अमानवीय नहीं जितना अमानवीय कृत्य उन्होंने किया है, इससे भी क्रूर यदि कोई दंड हो तो वो उन्हें मिलना चाहिए। पर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि यह है कि दंड मात्र दस्तावेज न बन कर रह जाए, तुरंत प्रभाव से इसे अमल में लाया जाना चाहिए।

shilpasurana48@gmail.com

कब जागेंगी सरकारें

फिरोजशाह कोटला मैदान पर श्रीलंका और भारत के बीच खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के लिए एक शर्मनाक घटना घटित हुई। मैच के दौरान फील्डिंग कर रहे श्रीलंका के खिलाड़ियों ने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिए। यहां खिलाड़ी यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की आबोहवा इतनी जहरीली और प्रदूषित हो चुकी है कि यहां आकर खेलना सेहत से खिलवाड़ है। विदेश की तरफ से यह पहली प्रमुख चेतावनी है। हो सकता है राजधानी में मौजूद अनेक दूतावास और हाई कमीशन दिल्ली की आबोहवा पर एतराज उठाकर यहां पर रहने से ही मना कर दें या कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधिमंडल यहां आने से मना कर दें। वायुप्रदूषण पर अभी तक असंवेदनशील केंद्र और विभिन्न प्रांतीय सरकारें अब भी न जगीं तो कब जगेंगी?

spgoel.jhm@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट